

		अनुसूची							(राशिरूपयोमे)	
मांग संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन	मुख्यशीर्ष	रशिया, जो निम्नलिखित से अधिक न हो		जोड़	मुख्यशीर्ष	रशिया, जो निम्नलिखित से अधिक न हो		जोड़	जोड़
		राजस्व	विधानसभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित		पूँजीगत	विधानसभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित		राजस्व और पूँजीगत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
05	गृह/ कारागार/गृहरक्षी और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)									
		2014-न्याय प्रशासन	...	60,09,57,000	60,09,57,000		60,09,57,000
		कुल	...	60,09,57,000	60,09,57,000		60,09,57,000
07	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां									
			6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	171,73,21,000	...	171,73,21,000	171,73,21,000
			कुल	171,73,21,000	...	171,73,21,000	171,73,21,000
08	लोक ऋण									
			6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	...	18536,00,00,000	18536,00,00,000	18536,00,00,000
			कुल	...	18536,00,00,000	18536,00,00,000	18536,00,00,000
12	शिक्षा (उच्चतर/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास									
		2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,00,000	...	2,00,000		2,00,000
		कुल	2,00,000	...	2,00,000		2,00,000
19	सिंचाई/उद्योग और वाणिज्य/ एमएसएमई/ पूर्ति तथा निपटान/ विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी									
		2801- बिजली	546,62,34,000	...	546,62,34,000		546,62,34,000
		कुल	546,62,34,000	...	546,62,34,000		546,62,34,000
		कुल जोड़	546,64,34,000	60,09,57,000	606,73,91,000	कुल जोड़	171,73,21,000	18536,00,00,000	18707,73,21,000	19314,47,12,000

THE SCHEDULE										
No of Demands	Services and purposes	Major Head	Sums not exceeding		Total	Major Head	Sums not exceeding		Total	Total (Revenue and Capital)
			Grants made by Legislative Assembly	Charged on the consolidated Fund			Grants made by Legislative Assembly	Charged on the consolidated Fund		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Revenue	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
05	Home / Prisons /Home Guard and Civil Defence / Administration of Justice (High Court / Prosecution /AGOT/ Legal Service Authority)									
		2014-Administration of Justice	...	60,09,57,000	60,09,57,000		60,09,57,000
		Total	...	60,09,57,000	60,09,57,000		60,09,57,000
07	Loans and Advances by State Government									
			6860-Loans for Consumer Industries	171,73,21,000	...	171,73,21,000	171,73,21,000
			Total	171,73,21,000	...	171,73,21,000	171,73,21,000
08	Public Debt									
			6003-Internal Debt of the State Government	...	18536,00,00,000	18536,00,00,000	18536,00,00,000
			Total	...	18536,00,00,000	18536,00,00,000	18536,00,00,000
12	Education (Higher/ Secondary/ Elementary)/ Technical Education/ Women and Child Development									
		2235-Social Security and Welfare	2,00,000	...	2,00,000		2,00,000
		Total	2,00,000	...	2,00,000		2,00,000
19	Irrigation/ Industries & Commerce/ MSME/ Supplies & Disposals/ Power & Renewable Energy/ Science & Technology									
		2801-Power	546,62,34,000	...	546,62,34,000		546,62,34,000
		Total	546,62,34,000	...	546,62,34,000		546,62,34,000
		Grand-Total	546,64,34,000	60,09,57,000	606,73,91,000	Grand-Total	171,73,21,000	18536,00,00,000	18707,73,21,000	19314,47,12,000

HARYANA BILL NO. 1 OF 2023

THE HARYANA APPROPRIATION (No. 1) BILL, 2023

A

Bill

to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Haryana for the services during the financial year ending on the thirty-first day of March, 2023.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy Fourth Year of the Republic of India as follows: -

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Appropriation (No.1) Act, 2023.

Issue of

₹19314,47,12,000/-

out of Consolidated

Fund of State of

Haryana for financial

year 2022-23.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Haryana, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 11 of the Schedule appended to this Act, amounting in the aggregate to the sum of Nineteen Thousand Three Hundred Fourteen Crore Forty Seven Lakh Twelve Thousand only (₹19314,47,12,000/-) towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2022-23 ending on the thirty-first day of March, 2023, in respect of the services specified in column 2 of the said Schedule.

Appropriation

3. The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Haryana by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ending on thirty- first day of March, 2023.

Statement of Objects and Reasons

The Bill is introduced in pursuance of articles 204 (1) and 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Haryana of the sums required to meet the supplementary grants made by the Legislative Assembly for expenditure for the financial year 2022-23.

Chief Minister, Haryana

2023 का हरियाणा विधेयक संख्या 1

हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023

मार्च, 2023 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और कतिपय राशियों का आगे भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹19314,47,12,000/- का दिया जाना।

2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक की ऐसी राशियां, जो कुल मिलाकर केवल उन्नीस हजार तीन सौ चौदह करोड़ सैंतालीस लाख बारह हजार रुपए केवल (₹19314,47,12,000/-) होती है, ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए, जो उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बारे में, मार्च, 2023 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होगी, हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी।

विनियोग।

3. इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो मार्च, 2023 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2022–23 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है ।

मुख्य मन्त्री, हरियाणा